भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 2190**

दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाकिस्तान द्वारा भारत को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा दिया जाना

2190. **श्री जय प्रकाश नारायण सिंहः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (एम॰एफ॰एन॰) का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एम॰एफ॰एन॰ दर्जा भेदभावपूर्ण उच्च कीमतों और ड्यूटी प्रशुल्क को दूर कर देगा जो दोनों देशों के बीच व्यापार में बाधा बनते हैं; और

(ग) वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच कितना वार्षिक व्यापार होता है तथा आगामी दो वर्षों के लिए व्यापार के क्या अनुमान है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया)

(क) दिनांक 2 नवम्बर, 2011 को पाकिस्तान सरकार की प्रेस रिलीज के जरिए सूचित पाकिस्तान मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि "मंत्रिमंडल (पाकिस्तान) ने वाणिज्य मंत्रालय को प्रसामान्यीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अधिदेशित किया है जिसकी परिणति सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (एम एफ एन) के सिद्धान्त के सही अर्थों में अनुसरण के रूप में होगी ।"

(ख) पाकिस्तान सरकार ने भारत से वस्तुओं के आयात के लिए दिनांक 20.3.2012 की अधिसूचना एस आर ओ संख्या 280(1)/2012 के जरिए 1963 मदों की सकारात्मक सूची को 1209 मदों की नकारात्मक सूची में परिवर्तित किया है । इस नकारात्मक सूची को वर्ष 2012 की समाप्ति से पहले पाकिस्तान सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने की संभावना है । सहमति यह बनी है कि जब एम एफ एन का दर्जा प्रभावी होगा तब साफ्टा के संवेदनशील सूची में दी गई सभी मदों के अलावा अन्य मदें वर्ष 2012 की समाप्ति तक 5% के अधिकतम टैरिफ स्तर पर अधिमानी पहुँच प्राप्त करेंगी ।

(ग) वर्ष 2010-11 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ा 2666.13 मिलियन अम.डा. का था । सितम्बर, 2011 में भारत के दौरे पर आए पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री के दौरे के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों तीन वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को 2.7 बिलियन अम.डा. प्रतिवर्ष के वर्तमान स्तर से लगभग 6 बिलियन डालर तक अर्थात दोगुने से अधिक करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत हुए हैं ।